



औद्योगिकीकरण का आर्थिक विकास पर प्रभाव

**सुमित कुमार, जाट

शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

*डॉ. राजबाला साईवाल, प्राचार्या

देव इंटरनेशनल कॉलेज, अलवर (राजस्थान)

भूमिका :

किसी भी देश अथवा प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है बल्कि भारतीय संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। इस प्रकार उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृहद् उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृहद् उद्योगों का प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। वृहद् उद्योग किस क्षेत्र में स्थापित होते हैं, उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास होकर आर्थिक विकास की संभावना बलवती हो जाती है।

सूचक शब्द :

प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने हेतु कई आर्थिक सुधार के कदम उठाये जा रहे हैं। चूंकि औद्योगिक विकास में सरकार का मुख्य उद्देश्य विकासयुक्त वातावरण सृजित करने का होता है। जिससे प्रेरित होकर अधिकाधिक उद्यमी अपना उद्योग प्रदेश में लगा सके। उद्योगों के विकास में अवस्थापना सुविधाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इसके दृष्टिगत सरकार द्वारा एक अलग अवस्थापना विकास विभाग की स्थापना की गयी है जिसका कार्य सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहभागिता के आधार पर विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है।

राजस्थान सरकार ने मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आधार पर प्रदेश में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) जयपुर, की स्थापना 1969 में की गई। इस संस्था के स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। रीको बड़े, मध्यम और लघु स्तर की परियोजनाओं को ऋण प्रदान करके एक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

अलवर जिले की नीमराना औद्योगिक क्षेत्र भारत के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक केन्द्रों में से एक है जिसके विकास का प्रमुख कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से निकटता और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (पुराना 8) पर स्थित होना तथा डी.एम.आई.सी. के निकट स्थित होना है। नीमराना जो प्राचीन ऐतिहासिक कस्बा है जहाँ राजस्थान ने रीको द्वारा 1992 से विभिन्न अवस्थाओं में औद्योगिक क्षेत्र में विकास किए हैं। रीको द्वारा यहाँ विशेष निर्यात जोन की स्थापना 2006 में की गई और इसके पश्चात् उद्योग लगाने के लिए नई—नई कम्पनियों का आगमन हुआ और जापानी जोन का विकास रीको द्वारा किया गया है। रीको द्वारा अब तक 45 जापानी कम्पनियों को 472 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है जिनमें 39 इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है आवंटन भूमि पर लगभग 4222 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं।

औद्योगिक विकास का दूसरा चरण 1990 के दशक से प्रारम्भ हुआ। इस चरण में नीमराना को औद्योगिक कस्बे के रूप में विकसित किया जाना था। विकास के इस चरण में वृहत् स्तर 960 एकड़ भूमि का अधिग्रहण औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु किया। नीमराना के इस प्रस्ताव के तहत् प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण पर कार्य किया गया। इस कस्बे में सभी 145 औद्योगिक प्लाट फुल हैं।

सन् 2013 में शाहजहाँपुर औद्योगिक केन्द्र के विस्तार का प्रस्ताव बना। यह विस्तार घिलोट तथा संलग्न गांव धीलोट, बटाणा, नागौड़ी, कुतीना, विघाना तथा दुंडारिया गांव में किया गया। साउथ कोरियन ट्रेड प्रोमोशन एजेन्सी के साथ बना। शाहजहाँपुर में पूर्ववत् 50 राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ कार्यरत हैं। कोट्रा को भी जापानी जोन के रेट पर भूमि उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ पर जापानी जोन की तर्ज पर कोरियन जोन 1700 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है।



नीमराणा का प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्थान उप क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित है। इस स्थल की कई विशेषतायें हैं। यह दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर 120 कि.मी. की दूरी पर तथा हरियाणा की सीमा के पास स्थित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-8 का इस क्षेत्र से गुजरने के कारण भी यहाँ पूँजी निवेश की विपुल सम्भावनायें होने के कारण अध्ययन क्षेत्र नगरीय समूह, अन्य शहरों से भली – भांति जुड़ा हुआ है।

पूँजी निवेश की विपुल सम्भावनायें होने एवं रीको द्वारा औद्योगिक विकास के स्थानीय लाभ को देखते हुए रीको द्वारा अध्ययन क्षेत्र के आसपास 7 औद्योगिक क्षेत्रों को कुल 3270.10 एकड़ भूमि में विकसित किया गया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2018–19 के प्लान के अनुसार 5500 करोड़ रु. का निवेश रखा गया था जिसमें से दिनांक 30 जनवरी, 2019 तक 1615 करोड़ रु. का निवेश कार्य पूर्ण किया गया।

रीको द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग में कुल बजट 3310.55 करोड़ रु. रखा गया जिनमें से 2930.00 करोड़ रु. का खर्च हुआ। वहीं वर्ष 2017–18 में कुल विभागीय बजट 4038.52 करोड़ रु. रखा गया जिनमें से 3939.02 करोड़ रु. खर्च किया गया। वर्ष 2017–18 में रीको द्वारा रखरखाव तथा विशेष रखरखाव के लिए 483.07 बजट रखा गया जिसमें से 74.77 प्रतिशत की रिकवरी की गई।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में अध्ययन क्षेत्र की प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुये शोध के दौरान आयी समस्याओं के समाधान को स्पष्ट करते हुए अध्ययन क्षेत्र के चयन को स्पष्ट किया गया। शोध से पूर्व निर्धारित की गयी परिकल्पनाओं को प्राप्त स्थान पर सिद्ध किया गया है। शोध के दौरान प्राथमिक आंकड़े, साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण, प्रश्नावली व अनुसूचियों के माध्यम से, द्वितीयक आंकड़े कार्यालयों से प्राप्त किये गये हैं। शोध के दौरान विभिन्न सन्दर्भित शोध-प्रबन्ध, किताबें, पत्र-पत्रिकाओं के साहित्य का अवलोकन कर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की गयी है।

शोध प्रारम्भ करने से पूर्व शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन को सात अध्यायों में विभाजित कर शोध का उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं का चयन किया। परिकल्पनाओं की सत्यता की पुष्टी यथास्थान शोध प्रबन्ध में सिद्ध की गयी है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति छह अध्यायों का विश्लेषण कर क्रमशः प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति की गयी है। समस्त अध्यायों से प्राप्त निष्कर्ष का विवरण इस अध्याय में किया गया है।

शोध क्षेत्र को अध्ययन में शोधार्थी द्वारा मुख्य नीमराणा की ग्राम पंचायत को विभाजित कर इनके जनांकिकी, भौगोलिकी स्वरूप, कार्यात्मक संरचना, उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर किया है। शोध क्षेत्र का अध्ययन करने के पश्चात् शोध प्रबंध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में विकसित औद्योगिक विकास का प्रभाव अध्ययन क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।

संदर्भ सूची :

1. गहलोत, जगदीश सिंह : राजपूताने का इतिहास, भाग-13
2. जिफ, जी. के. : ह्यूमन बिहेवियर एण्ड दी प्रिंसिपल ॲफ लीस्ट एफर्ट, कैम्ब्रिज।
3. देरा श्री, सत्यदेव : (अ) भारतीय अर्थशास्त्र (ब) उच्चतर माध्यमिक अर्थशास्त्र, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, हॉस्पिटल रोड, आगरा।
4. पीटर, एन. : प्लानिंग ॲफ इंडस्ट्रीयल काम्पलैवर्सज बाई मीन्स ॲफ ज्योमैट्रिक प्रोग्रामिंग, रोटरडन, 1972
5. वर्थपाल, आर.आर. : इंडस्ट्रीयल इकानोमिक्स-विले इस्टर्न लिमिटेड, देहली, 1984